ई-न्यूज

# 24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, मंगलवार 28 जुलाई 2026

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 3 अंक 101

पृष्ठ 4

# जापान फिर दहला: 6.8 तीव्रता के भूकंप से तबाही, मॉल ढहा; 50 से ज्यादा लोग मलबे में, 1.5 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू

24 न्यूज अपडेट

टोक्यो/ कुमामोटो। भूकंपों की मार झेलने का लंबा अनुभव रखने वाला जापान मंगलवार को एक बार फिर भीषण आपदा से दहल उठा। दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में आए 6.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कुछ ही मिनटों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। काशिमा शहर में एक बहुमंजिला शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल भरभराकर ढह गई, जहां 50 से अधिक लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। कई लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जबकि राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार भूकंप मंगलवार शाम 4:27 बजे (स्थानीय समय) आया। इसका केंद्र राजधानी टोक्यो से करीब 900 किलोमीटर दूर कुमामोटो प्रांत में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। झटके इतने तेज थे कि सड़कों में दरारें पड़ गईं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए, कई इमारतों में आग लग गई और ऐतिहासिक कुमामोटो कैसल की दीवारों का हिस्सा भी ढह गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने क्यूशू द्वीप के 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में भेजने के निर्देश दिए। शुरुआती सुनामी चेतावनी जारी की गई, हालांकि लगभग एक घंटे बाद इसे वापस ले लिया गया।

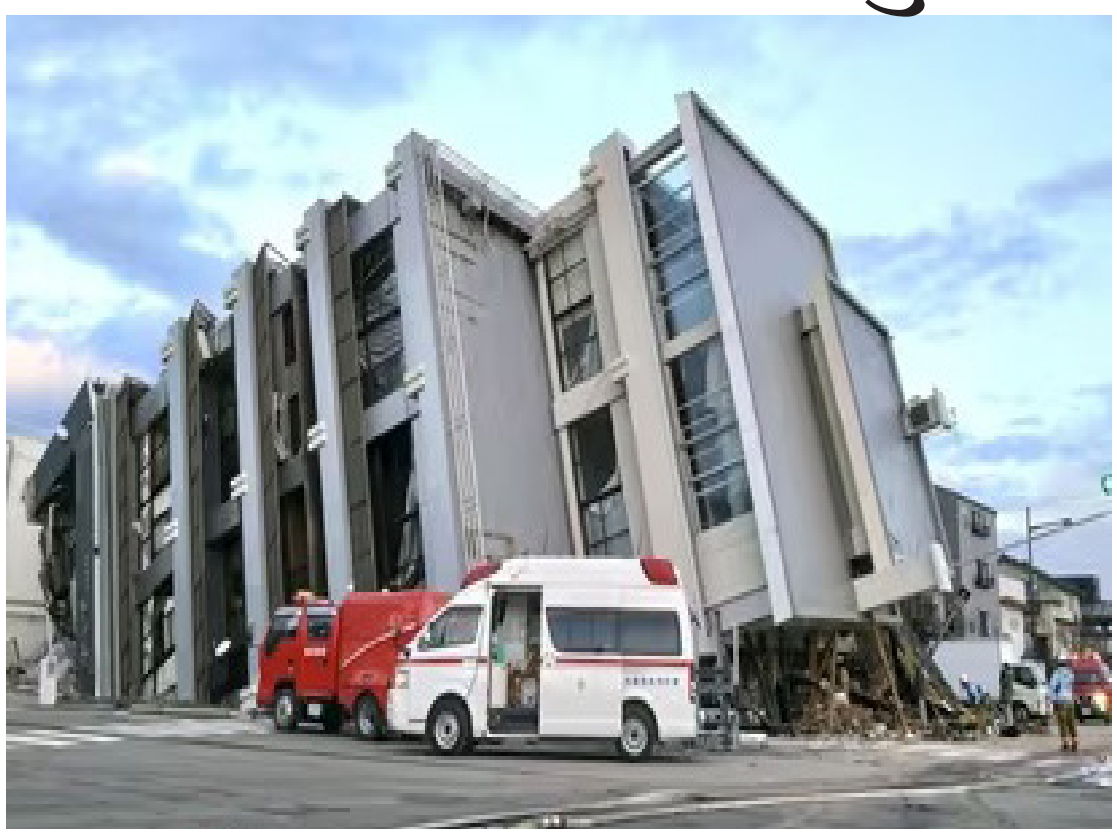

### मॉल में धमाके के बाद बढ़ी तबाही

भूकंप के कुछ समय बाद काशिमा स्थित शॉपिंग मॉल में धमाका हुआ, जिससे इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। दमकल विभाग और बचाव एजेंसियां मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटी हैं। अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है।

### 3,600 सैनिक राहत अभियान में तैनात

प्रधानमंत्री साने ताकइची ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में 3,600 सैन्यकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के अतिरिक्त जवान भी राहत कार्य में लगाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

### 60 से अधिक आफ्टरशॉक, बिजली भी ठप

मुख्य भूकंप के बाद अब तक 60 से ज्यादा आफ्टरशॉक दर्ज किए जा चुके हैं। कुमामोटो में 48,300 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। एहतियात के तौर पर बुलेट ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं, जिससे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई।

### परमाणु संयंत्र सुरक्षित

जापान की न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को बताया कि सेंदाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुरक्षित है और वहां किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। 2011 की फुकुशिमा त्रासदी के बाद जापान में हर बड़े भूकंप के दौरान परमाणु संयंत्रों की विशेष निगरानी की जाती है।

### दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों में जापान

जापान प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है और चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है। यहां हर वर्ष करीब 1,500 भूकंप दर्ज होते हैं। हालांकि भूकंपरोधी निर्माण, अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली और तेज राहत तंत्र के कारण बड़े हादसों में जनहानि अपेक्षाकृत कम रहती है। अब पूरी दुनिया की नजर कुमामोटो में चल रहे राहत अभियान पर टिकी है, जहां मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए समय के साथ जंग जारी है।

## PM मोदी का हटाया गया फेसबुक वीडियो फिर हुआ बहाल, META बोली- तकनीकी गड़बड़ी थी

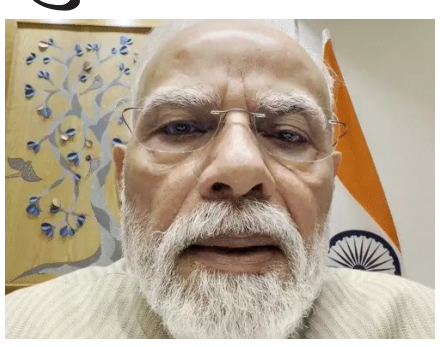

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा सुधार और पेपर लीक पर जारी किया गया वीडियो फेसबुक से हटने के कुछ समय बाद META ने दोबारा रीस्टोर कर दिया। कंपनी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो गलती से हट गया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। यह वीडियो 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने छात्रों और जेन-जी को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दोषियों की गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भरोसा दिया था। कुछ समय तक फेसबुक पर वीडियो की जगह "यह वीडियो भारत में उपलब्ध नहीं है" का संदेश दिखाई देने लगा, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। इस बीच, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MEITY) ने मामले पर स्पष्टीकरण के लिए META के ग्लोबल हेड और पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को तलब किया है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके परिवारों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया था कि पिछले ढाई महीनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई और अब इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद 24 जुलाई को मोदी ने वीडियो पर मिले सुझावों के लिए लोगों का धन्यवाद दिया था, जबकि 26 जुलाई को परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाईपावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा करते हुए पेपर लीक पर और सख्त कानून लाने का संकेत दिया था।

## शिक्षामंत्री पर प्रियंका के बयान से संसद में तूफान, 'बलात्कारियों का बचाव करने वाले को बनाया मंत्री', टिप्पणी पर हंगामा; रिजिजू बोले- माफी मांगें, प्रियंका बोलीं- सबूत दूंगी

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। पेपर लीक रोकने से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026' पर लोकसभा में मंगलवार को चर्चा के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी पर बिलकिस बानो मामले का हवाला देते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। प्रियंका ने कहा कि "सरकार ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षामंत्री बनाया जिसने गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था।" इस बयान पर सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया और माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, प्रह्लाद जोशी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे शिक्षामंत्री का चरित्र हनन बताते हुए कहा कि प्रियंका या तो अपने आरोपों के सबूत पेश करें या सदन से माफी मांगें। इस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि उनके पास बयान के प्रमाण हैं और वे सदन को उपलब्ध करा देंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रियंका गांधी को बिना तथ्य ऐसे आरोप लगाने से बचने की नसीहत दी और सदस्यों से विधेयक पर ही चर्चा करने को कहा। बाद में चर्चा का समय छह घंटे से बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "देश का शिक्षामंत्री ऐसा व्यक्ति है जिसने बलात्कारियों का बचाव किया।" भाजपा ने इस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई।

## 30 लाख की रिश्वत केस में 10 महीने से फरार पटवारी गिरफ्तार, 'डिजिटल उपवास' भी नहीं बचा सकी

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 30 लाख रुपए की रिश्वत मामले में पिछले 10 महीने से फरार चल रहे पटवारी नरेंद्र मीणा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एसीबी से बचने के लिए पूरी तरह 'डिजिटल उपवास' पर चला गया था। उसने ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप और यहां तक कि परिजनों व दोस्तों से भी संपर्क बंद कर दिया था, लेकिन एसीबी ने पारंपरिक पुलिस नेटवर्क की मदद से उसे दबोच लिया। एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी पटवारी नरेंद्र मीणा, निवासी चंपापुरा (हाथोज, जयपुर), नामांतरण के एक मामले में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। बाद में 30 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई और 5 लाख रुपए असली तथा 25 लाख रुपए के डमी नोटों के साथ कार्रवाई की। हालांकि, पटवारी खुद रिश्वत लेने नहीं पहुंचा और अपने दलाल विकास शर्मा को भेज दिया। एसीबी ने दलाल को मौके पर ही रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि ट्रैप की भनक लगते ही नरेंद्र मीणा फरार हो गया। डीआईजी ने बताया कि फरारी के दौरान आरोपी ने किसी भी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यूपीआई, सोशल मीडिया और मोबाइल संपर्क तक बंद कर दिए, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना चुनौती बन गया। एसीबी के डीएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए उसके पुराने ठिकानों और परिचितों पर लगातार नजर रखी। आखिरकार आरोपी के कालवाड़ स्थित गांव चंपापुरा आने की सूचना मिलने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

## एमडीएमए के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर लेकर नेटवर्क खंगालने में जुटी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 4.31 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए (MDMA) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब उससे मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश ओझा तथा नगर पूर्व वृत्ताधिकारी छवि शर्मा के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार 27 जुलाई को थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान टीम देबारी चौकी से घाटावाला माताजी जाने वाले पुराने मार्ग पर पहुंची। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रामलाल (23) पुत्र प्रभुलाल, निवासी गंदोली, थाना घासा, जिला उदयपुर बताया। संदिग्ध गतिविधियों के चलते नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 4.31 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में प्रतापनगर थाने में प्रकरण संख्या 407/ 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 22 में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद तीन दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हुई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने एमडीएमए कहां से खरीदा, किसे सप्लाई करता था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

कार्रवाई में प्रतापनगर थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में गठित टीम में उपनिरीक्षक अशोक कुमार सिंह, कांस्टेबल भंवरलाल, कमलेश कुमार एवं विशाल चंद की सक्रिय भूमिका रही।

## पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करने का हाईकोर्ट का आदेश

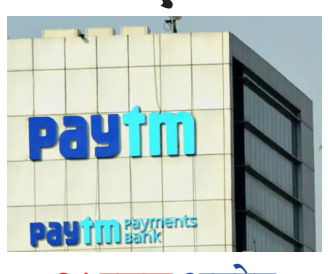


24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ महीनों बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। बैंक के परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम. नायर को बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है। RBI ने मंगलवार को बताया कि हाईकोर्ट के 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के आदेशों के तहत यह कार्रवाई की गई है। अदालत ने लिक्विडेटर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियां सौंप दी हैं। नायर 8 जुलाई से ही बैंक के संचालन और परिसमापन प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। RBI ने स्पष्ट किया कि बैंक का लाइसेंस अप्रैल 2026 में लगातार नियामकीय नियमों के उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों की अनदेखी के कारण रद्द किया गया था। उस समय केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया था कि वह बैंक को बंद कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा।

## संपादकीय : दमन की राह

एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता को किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जाहिर करने का अधिकार होता है और सरकार को इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए । जब भी जनता के किसी हिस्से में सरकार के रुख की वजह से असंतोष पैदा हो, तो यह जिम्मेदारी सरकार की ही होती है कि वह संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाले । मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि अगर सरकार की उदासीनता की वजह से लोग अपनी बात कहने सड़क पर उत्तरें, तो उन्हें रोकने के लिए बातचीत की गुंजाइश निकालने के बजाय दमन का रास्ता अख्तियार किया जाए। नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर जब विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की, तो सरकार के पास वक्त था कि वह संवाद के जरिए एक आदर्श समाधान सामने रखे। अगर इस दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका होती, तो उसे नियंत्रित करने के लिए भी हर वह विकल्प आजमाए जाने चाहिए थे, जिससे प्रदर्शन बेलगाम न हो और न ही पुलिस को हिंसक बलप्रयोग करने की जरूरत पड़े। मगर अपनी मांगों के साथ 'संसद मार्च' का आह्वान करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई, उससे यह सवाल उठा है कि सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे और जनता के संवैधानिक अधिकारों को कैसे देखती है। गौरतलब है कि नीट प्रश्नपत्र लीक होने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। मगर इस क्रम में ज्यादा गंभीर आरोप यह सामने आया कि आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से पेलेट गन भी चलाया गया। वहीं पुलिस के इस रवैये के विरोध में जब देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हुए, तो वहां भी गैरजरूरी तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया गया। एक अन्य आरोप के मुताबिक, बिहार के सिवान में एक पुलिसकर्मी ने एके-47 राइफल से विद्यार्थियों पर गोलियां चलाईं। सवाल है कि महज प्रश्नपत्र लीक होने के मसले पर अपना विरोध जताने वालों के खिलाफ घातक हथियार चलाने की हद तक जाकर पुलिस आखिर क्या संदेश देना चाहती है। क्या ऐसे आरोपों के बाद अनिवार्यता की दलील पर विद्यार्थियों के खिलाफ ऐसे बर्ताव को उचित ठहराया जा सकता है ? यों आज के दौर में अमूमन हर सार्वजनिक गतिविधि की जीवंत तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह के आरोप भी लगे, तो क्या यह संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर सवालिया निशान नहीं हैं ? कायदे से अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों को लेकर सरकार को खुद सजग रहना चाहिए था। मगर विचित्र है कि यह सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण और कानूनसम्मत प्रदर्शन का अधिकार संविधान के हाथों संरक्षित है और केवल आंदोलन करने के आधार पर लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन खत्म होने के बाद कई जगहों से ऐसी खबरें आईं कि हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा कर कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह आंदोलनकारियों से किए गए वादे से सरकार के मुकरने की तरह है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह बेवजह नहीं है कि विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका मिला है कि पूरा तंत्र विद्यार्थियों के खिलाफ जानलेवा तरीके से खड़ा है।

## लापरवाही की कड़ियां

यह विचित्र बात है कि एक तरफ भारत अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, मशीनीकरण और कृत्रिम मेधा पर भी खासा जोर दिया जा रहा है, दूसरी ओर गंदे नालों और सीवेज टैंक की सफाई आज भी बिना सुरक्षा उपकरणों के हाथ से कराई जा रही है, जो कई बार मौत का कारण बन जाती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 150 में बीते शनिवार की रात को हुई, जब सीवेज टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक श्रमिक और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। आखिर क्या कारण है कि तमाम दिशा-निर्देशों और नियम-कानून के बावजूद उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है ? क्या इसकी वजह यह है कि सफाई कार्य से जुड़े लोग समाज के निचले और कमजोर तबके के होते हैं, जिनकी शासन-प्रशासन तक सीधी पहुंच नहीं होती है ! अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इन श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपायों के जोखिम भरे कार्य में कैसे शोक दिया जाता है? सरकार की ओर से बीते मार्च में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से देश में सीवर और सीवेज टैंक की सफाई के दौरान करीब 622 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 539 परिवारों को ही पूरा मुआवजा मिल पाया। ये वे आंकड़े हैं, जिन घटनाओं की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई, मगर इससे कहीं अधिक मामले ऐसे होते हैं, जो कहीं दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे में न तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है और न ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल पाती है। देश में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर वर्ष 2013 में कानून बनाया गया था इसके तहत किसी व्यक्ति को सीवर या सीवेज टैंक में बिना सुरक्षा मानकों के उतारना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में एक अहम फैसले में कहा था कि इस तरह के कार्य के दौरान होने वाली हर मौत के लिए सरकार जवाबदेह है। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो यह सीधे तौर पर शासन-प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है।

# राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: अब प्रसूताओं को बिना रिप्लेसमेंट मिलेगा मुफ्त ब्लड, अस्पतालों को दिए सख्त निर्देश

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान में प्रसूताओं की बिगड़ती तबीयत और कुछ मामलों में हुई मौतों के बाद राज्य सरकार ने मातृ स्वास्थ्य को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में भर्ती गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को जरूरत पड़ने पर बिना रिप्लेसमेंट के मुफ्त रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और अन्य ब्लड कॉम्पोनेंट भी निशुल्क दिए जाएंगे। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर सभी सरकारी ब्लड बैंकों को तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब तक अधिकांश मामलों में मरीज के परिजनों को ब्लड के बदले रिप्लेसमेंट डोनर की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं को इस प्रक्रिया से राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रक्त की अनुपलब्धता के कारण किसी भी महिला के इलाज में देरी न हो। हालांकि सरकार के इस फैसले के साथ सरकारी ब्लड बैंकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बीच प्लेटलेट्स और रक्त की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि हाल के समय में रक्तदान शिविरों की संख्या कम हुई है। ऐसे में पर्याप्त ब्लड स्टॉक बनाए रखना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसी को देखते हुए राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने सभी सरकारी ब्लड बैंकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप की कमी नहीं होने दी जाए। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों, एनजीओ, कॉलेजों और स्वैच्छिक रक्तदाताओं के साथ समन्वय बढ़ाने, नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से प्रसूताओं को समय पर रक्त उपलब्ध होगा और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी।

## नगर निगम ई-पब्लिक लाइब्रेरी में एम.लिब. के विद्यार्थियों को मिला आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन का प्रशिक्षण

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। नगर निगम की अशोक नगर स्थित ई-पब्लिक लाइब्रेरी में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (एमएलएसयू) के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (एम.लिब.) के छह विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के तहत प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को पारंपरिक पुस्तकालय व्यवस्था के साथ-साथ आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी प्रबंधन की तकनीकों से भी परिचित कराया जा रहा है। ई-पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालयाध्यक्ष राव भगवत सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले वर्ष से इंटर्नशिप अनिवार्य किए जाने के बाद नगर निगम ई-पब्लिक लाइब्रेरी विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाला प्रमुख केंद्र बन गई है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को Classified Catalogue Code के अनुसार कैटलॉग कार्ड तैयार करना, डॉ. एस.आर. रंगनाथन की Colon Classification पद्धति से पुस्तकों का वर्गीकरण, क्लास नंबर के अनुसार पुस्तकों को रैक में व्यवस्थित करना, शेल्विंग और शेल्फ रेक्टिफिकेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को SOUL (Software for University Libraries) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सदस्य पंजीकरण, कैटलॉगिंग, वर्गीकरण, एक्सेशन, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी, OPAC Search और रिपोर्ट जनरेशन जैसे दैनिक पुस्तकालय कार्यों का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में RFID (Radio Frequency Identification) तकनीक की भी विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को RFID Tagging, Self Check-in/ Self Check-out, Book Drop Box, Security Gate, Handheld Reader, Inventory Verification और Shelf Management जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं का संचालन सिखाया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों को Reference Service, Reading Hall, Digital Library, E-Resources, समाचार पत्र एवं पत्रिका अनुभाग, प्रतियोगी परीक्षा कॉर्नर, सदस्यता सेवाओं और यूजर ओरिएंटेशन की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान पुस्तकालय में उपलब्ध निःशुल्क वाई-फाई, वातानुकूलित अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर सुविधा, आरओ एवं यूवी शुद्ध पेयजल सहित अन्य सुविधाओं से भी अवगत कराया गया। राव भगवत सिंह ने बताया कि पुस्तकालय में 10 करोड़ से अधिक ई-बुक्स और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। इंटर्नशिप में शामिल विद्यार्थियों ने कहा कि नगर निगम ई-पब्लिक लाइब्रेरी में मिला प्रशिक्षण उनके लिए अत्यंत उपयोगी रहा।

## ताराचंद मीणा आदिवासी कांग्रेस की राज्य सलाहकार परिषद में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 28 जुलाई। उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे एवं पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को राजस्थान प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की राज्य सलाहकार परिषद में विशेष आमंत्रित सदस्य (स्पेशल इनवाइटी) नियुक्त किया गया है। नियुक्ति अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष एवं झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने की। डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि ताराचंद मीणा का प्रशासनिक अनुभव, संगठन के प्रति प्रतिबद्धता और मार्गदर्शन कांग्रेस को मजबूत करने के साथ-साथ आदिवासी समाज के हितों, कल्याण और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नियुक्ति के बाद ताराचंद मीणा ने जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉ. विक्रांत भूरिया से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और इस जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व एवं डॉ. भूरिया का आभार व्यक्त किया। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी दिनेश औदिच्य ने बताया कि संगठन को उम्मीद है कि ताराचंद मीणा के अनुभव का लाभ आदिवासी कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मिलेगा।

## शर्मा को महानगर में संगठन मंत्री का दायित्व

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन की बैठक कार्यालय पर ग्राहक पंचायत के प्रांत संगठन मंत्री राकेश पालीवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई । यह जानकारी पंचायत के जिला मंत्री नारायण पंचोली ने देते हुए बताया कि पंचायत की सदस्यता अभियान अगस्त में आरंभ किया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ा जाएगा । बैठक में जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने ग्राहक पंचायत के महानगर में परमानंद शर्मा को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया । बैठक में करणसिंह कटारिया, सूर्य प्रकाश पालीवाल, हरीशंकर तिवारी,मांगीलाल भोई, नरपत सिंह कुमावत, सत्यनारायण प्रजापत, डॉ. कुणाल आमेटा, जय प्रकाश भावसार आदि ने संबोधित किया।

## माहेश्वरी महिला गौरव क्लब की सदस्यों ने लिया 'एक पौधा गुरु के नाम' का संकल्प

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 28 जुलाई। माहेश्वरी महिला गौरव क्लब की ओर से गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस पर माहेश्वरी महिला गौरव क्लब की संरक्षक कौशल्या गट्टानी के मार्गदर्शन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय शोभागपुरा विद्यालय में गुरुवंदन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लब की अध्यक्ष सीमा लाहोटी ने बताया कि कार्यक्रम में क्लब की सदस्याओं ने विद्यालय के शिक्षकों का तिलक लगाकर, उपरणा ओढ़ाकर, श्रीफल एवं मिठाई भेंट कर गुरुवंदन किया और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात एक पौधा गुरु के नाम संकल्प के तहत विद्यालय परिसर में छायादार फूल वाले वृक्ष लगाए गए। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। सचिव रेखा देवपुरा ने बताया कि निर्मला काबरा, कला गट्टानी, रेणु मूंदड़ा, बच्चों को पेंसिल, रबर, बिस्कुट, चॉकलेट इत्यादि का वितरण किया। इस अवसर पर आशा नारायणीवाल, अंकिता मंत्री, कविता बल्दवा, मनोरमा, अनीता, सरिता मूंदड़ा , इंदिरा मूंदड़ा सहित अन्य सदस्याएँ एवं विद्यालय परिवार के शिक्षक व बच्चे उपस्थित रहे।

## गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशभर में 516 संतों का होगा सम्मान

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 28 जुलाई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देवस्थान विभाग 29 जुलाई को प्रदेशभर में 'गुरु वंदन कार्यक्रम' आयोजित करेगा। कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 516 संतों और महंतों का उनके आश्रम, मठ एवं मंदिरों में जाकर सम्मान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष 'गुरु वंदन संदेश' भी उन्हें भेंट किया जाएगा। देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सभी जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की मौजूदगी में चिन्हित मठों और मंदिरों में पहुंचकर संत-महंतों का सम्मान एवं अभिनंदन करेंगे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुजनों, संतों और महंतों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। सम्मान स्वरूप संत-महंतों को मुख्यमंत्री की ओर से 'गुरु वंदन संदेश', श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई तथा 2,100 रुपये की सम्मान राशि भेंट कर अभिनंदन किया जाएगा।

## एमपीयूएटी के अंशुल शर्मा ने पीएचडी पूरी की

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) के राजस्थान कृषि महाविद्यालय के शस्य विज्ञान विभाग के शोधार्थी अंशुल शर्मा ने डॉ. अरविंद वर्मा के मार्गदर्शन में मक्का की वृद्धि एवं उपज पर सिलिका एवं वर्मीकम्पोस्ट के प्रभाव विषय पर अपना पीएचडी शोध सफलतापूर्वक पूर्ण किया। शोध में सिलिका एवं वर्मीकम्पोस्ट के संतुलित उपयोग को मक्का उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य सुधार, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा टिकाऊ कृषि के लिए प्रभावी बताया गया। यह शोध प्रधानमंत्री डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत प्राप्त अनुसंधान सहायता से पूरा हुआ। अंशुल शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, प्रमुख सलाहकार डॉ. अरविंद वर्मा, विभाग के शिक्षकों, विश्वविद्यालय प्रशासन एवं सहयोगियों को दिया। जानकारी रामनारायण कुम्हार, मीडिया प्रकोष्ठ एवं सह जनसंपर्क अधिकारी, एमपीयूएटी ने दी।

# सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, 4 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने मंगलवार को प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान चार छात्र प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बताया गया कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में पेयजल और नहाने-धोने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आर्ट्स और लॉ कॉलेज के वाटर कूलर की नियमित सफाई नहीं होने से छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्रदर्शन की सूचना पर प्रतापनगर थानाधिकारी अजयसिंह राव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसी प्रकार प्रस्तावित मराठी भाषा केंद्र का विरोध करते हुए कहा कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मराठी भाषा केंद्र खोला गया तो उसका विरोध किया जाएगा। छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने की मांग करते हुए कहा कि निर्वाचित छात्रसंघ ही छात्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सकता है। हॉस्टलों में बिजली-पानी की समस्या, जर्जर भवन और अभिभावकों के बैठने की व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने "हमारी मांगें पूरी करो" और "आवाज दो, हम एक हैं" जैसे नारे लगाए।

## चाकू की नोक पर स्कूटी लूटने वाले दो शातिर बदमाश 2 घंटे में गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीटर निकले आरोपी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 28 जुलाई। उदयपुर पुलिस ने गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में राहगीर से चाकू की नोक पर स्कूटी, नकदी और सोने की अंगूठी लूटने की सनसनीखेज वारदात का महज दो घंटे में खुलासा करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अम्बामाता थाना क्षेत्र का हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर मोईन उर्फ धुरी और उसका साथी इदरीस उर्फ छोटू शामिल हैं। पुलिस ने लूटी गई स्कूटी बरामद कर ली है, जबकि वारदात में प्रयुक्त स्कूटी, लूटी गई नकदी और सोने की अंगूठी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा के सुपरविजन तथा वृत्ताधिकारी गोपाल चंदेल के निर्देशन में गोवर्धनविलास थानाधिकारी सुनील चारण के नेतृत्व में गठित टीम ने की।

### आधी रात को लौट रहे थे, रास्ता रोककर की लूट

पुलिस के अनुसार अहमदाबाद निवासी गौरव कुमार सिंधी और उनके साथी विनोद कुमार चेतनानी पिछले कुछ दिनों से जीवनतारा क्षेत्र में किराये पर रह रहे हैं। मंगलवार देर रात दोनों किराये की स्कूटी से उदियापोल नाश्ता करने गए थे। लौटते समय करीब 1:20 बजे बड़बड़ेश्वर महादेव रोड के पास बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर आए दो युवकों ने उनका पीछा किया। सुनसान गली में आरोपियों ने उनकी स्कूटी के आगे अपनी स्कूटी लगाकर रास्ता रोक लिया। पीछे बैठे बदमाश ने बड़ा चाकू निकालकर दोनों को नीचे उतार दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित से करीब 20 हजार रुपये नकद, सोने की अंगूठी और उनकी स्कूटी लूटकर फरार हो गए।

### शहरभर में नाकाबंदी, मल्लातलाई से दबोचे गए

घटना की सूचना मिलते ही गोवर्धनविलास थाना पुलिस सक्रिय हुई। पीड़ितों से मिले हुलिए और संदिग्धों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने शहरभर में नाकाबंदी करवाई। दोनों आरोपियों के आदतन अपराधी होने और पुलिस रिकॉर्ड में पहले से दर्ज होने के कारण उनकी तलाश तेज की गई। लगातार पीछा करते हुए पुलिस टीम ने अम्बामाता थाना क्षेत्र के मल्लातलाई इलाके में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने वारदात स्वीकार कर ली, जिसके बाद लूटी गई स्कूटी बरामद कर ली गई। पूरी कार्रवाई घटना के करीब दो घंटे के भीतर पूरी कर ली गई।

### दोनों के खिलाफ दर्ज हैं कई गंभीर मुकदमे

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोईन उर्फ धुरी (23) अम्बामाता थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती की तैयारी, हथियार अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट, अपहरण, मारपीट, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दूसरा आरोपी इदरीस उर्फ छोटू (21) भी लूट और मारपीट सहित कई संगीन मामलों में आरोपी रहा है। उसके खिलाफ अम्बामाता, गोवर्धनविलास, हिरणमगरी और नाई थाना क्षेत्रों में एकाधिक लूट और अन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं।

### संगठित अपराध की धाराएं भी लगेंगी

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी आदतन और संगठित अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उनके विरुद्ध बीएनएस की संगठित अपराध संबंधी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की जांच जारी है।

### कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम

गोवर्धनविलास थाना प्रभारी सुनील चारण के नेतृत्व में देवेन्द्र पुरी, धर्मवीर सिंह, प्रदीप कुमार, कालूलाल, अंकित सिंह, शैतानराम और कैलाश कुमार की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

## 7 अगस्त से सजेगा 'जैनम-15', 100 से ज्यादा स्टॉल्स पर मिलेगी देशभर की शॉपिंग

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जैन जागृति सेंटर महिला शाखा की ओर से तीन दिवसीय 'जैनम-15' एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन 7 से 9 अगस्त तक शोभागपुरा स्थित ओकेजन बैंक्विट हॉल में होगा। संरक्षिका पिंकी माण्डावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत के साथ विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। संयोजिका सुमन लुणदिया ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, पाली, अहमदाबाद और अजमेर सहित देशभर से 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे। यहां डिजाइनर राखियां, सेठी व पारंपरिक साड़ियां, बंधेज, चिकनकारी, लाख की चूड़ियां, सिल्वर ज्वेलरी, फुटवियर, होम डेकोर, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपलब्ध रहेंगे। सह संयोजिका सुशीला मेहता ने बताया कि बच्चों के लिए राखी मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप, गेम जोन, महिलाओं के लिए तंबोला-हाउजी तथा फूड कोर्ट भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। बैठक में प्रणीता तलेसरा, बीना मारू और वंदना जैन सहित महिला शाखा की पदाधिकारी एवं सदस्याएं मौजूद रहीं।

## सरकारी अस्पतालों में दवा-जांच व्यवस्था सुधारने की मांग, पेंशनर्स महासंघ ने सरकार को घेरा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर्स महासंघ ने सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और जांच सुविधाओं की अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष इंजी. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी और महामंत्री इंजी. अरविन्द कौशल ने कहा कि सरकारी आदेशों के बावजूद मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे पेंशनर्स और आम जनता आर्थिक बोझ झेल रही है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आर.एस. चावड़ा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार भटनागर, डॉ. अरुण कुमार शर्मा, मनफूल मंगल्या और मूलचन्द जाट ने कहा कि आरजीएचएस से जुड़े कई निजी मेडिकल स्टोर भुगतान में देरी के कारण दवाइयां देने से इंकार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश मंत्री डॉ. भरत सिंह भीमावत, नेमाराम, मोहनलाल चांगवाल, महावीर शर्मा और डॉ. भूपेन्द्र उपाध्याय ने निजी डायग्नोस्टिक व इमेजिंग सेंटरों के शीघ्र सूचीबद्धीकरण और जांच खर्च के समयबद्ध पुनर्भरण की मांग उठाई। प्रदेश संगठन मंत्री इंजी. सुरेन्द्र भूषण सहाय ने कहा कि पर्याप्त बजट, स्थानीय स्तर पर दवा खरीद, जांच सुविधाओं का विस्तार और विभागीय आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाए। महासंघ ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।

## मच्छरजनित बीमारियों पर निगम का अभियान आज से, लापरवाही पर लगेगा जुर्माना

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। नगर निगम शहर में डेंगू, मलेरिया सहित मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए बुधवार से व्यापक जनजागरण अभियान शुरू करेगा। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा तय की और शहरवासियों से घरों व आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की। आयुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा के निर्देशन में सेक्टर अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादार और सफाईकर्मी घर-घर जाकर लोगों को कूलर, टंकियों, गमलों व अन्य स्थानों पर जमा पानी नियमित रूप से बदलने और लार्वा नहीं पनपने देने के लिए जागरूक करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. विक्रम सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने चेतावनी दी कि समझाइश के बावजूद लापरवाही मिलने पर नगर निगम नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूलेगा।

## PTI भर्ती में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाकर बना शिक्षक, फरार आरोपी आखिरकार गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (PTI) भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी से अपनी जगह परीक्षा दिलाकर चयन पाने वाले आरोपी को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में सिविल लाइंस थाना पुलिस और विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जालोर जिले के कूका गांव निवासी गोपिलाला बिश्नोई (33) को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2022 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज था। पुलिस जांच में सामने आया कि गोपिलाला बिश्नोई ने PTI भर्ती परीक्षा-2022 में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाया था। इसी फर्जीवाड़े के जरिए उसका चयन भी हो गया। बद में दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, परीक्षा देने वाला डमी अभ्यर्थी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

# सरकारी अस्पतालों में दवा-जांच व्यवस्था सुधारने की मांग, पेंशनर्स महासंघ ने सरकार को घेरा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर्स महासंघ ने सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और जांच सुविधाओं की अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष इंजी. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी और महामंत्री इंजी. अरविन्द कौशल ने कहा कि सरकारी आदेशों के बावजूद मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे पेंशनर्स और आम जनता आर्थिक बोझ झेल रही है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आर.एस. चावड़ा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार भटनागर, डॉ. अरुण कुमार शर्मा, मनफूल मंगल्या और मूलचन्द जाट ने कहा कि आरजीएचएस से जुड़े कई निजी मेडिकल स्टोर भुगतान में देरी के कारण दवाइयां देने से इंकार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश मंत्री डॉ. भरत सिंह भीमावत, नेमाराम, मोहनलाल चांगवाल, महावीर शर्मा और डॉ. भूपेन्द्र उपाध्याय ने निजी डायग्नोस्टिक व इमेजिंग सेंटरों के शीघ्र सूचीबद्धीकरण और जांच खर्च के समयबद्ध पुनर्भरण की मांग उठाई। प्रदेश संगठन मंत्री इंजी. सुरेन्द्र भूषण सहाय ने कहा कि पर्याप्त बजट, स्थानीय स्तर पर दवा खरीद, जांच सुविधाओं का विस्तार और विभागीय आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाए। महासंघ ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।

## 'मोबाइल मेला' में 281 लोगों की लौटी मुस्कान, एसपी ने लौटाए गुम और चोरी हुए फोन

24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पुलिस के जन सहायता अभियान के तहत मंगलवार को एसपी कार्यालय में आयोजित 'मोबाइल मेला' में गुम और चोरी हुए 281 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल प्राप्त करने वालों में दिनेश बलाई ने बताया कि उनका मोबाइल 18 मई को रोडवेज बस स्टैंड के पास गुम हो गया था। उन्होंने 19 मई को सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस का फोन आया और उन्हें उनका मोबाइल वापस मिल गया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को फोन सौंपे। उन्होंने बताया कि यह पुलिस का जन सहायता कार्यक्रम है, जिसके तहत गुम या चोरी हुए मोबाइल तकनीकी जांच के जरिए तलाश कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए जाते हैं। एसपी ने बताया कि सभी 281 मोबाइल पुलिस की विशेष टीम और साइबर टीम ने तकनीकी सहायता से बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले में मोबाइल रिकवरी दर 70.8 प्रतिशत है। चोरी के मामलों में अलग से विशेष टीम गठित कर मोबाइल चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य, साइबर टीम के सदस्य और बड़ी संख्या में मोबाइल मालिक मौजूद रहे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ फोन फिर से मिल पाएगा।

## OTP की एक गलती, 1.02 लाख की साइबर ठगी... लेकिन 1930 पर शिकायत ने बचा ली पूरी रकम

24 न्यूज अपडेट

चित्तौड़गढ़। एक महिला क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने फोन पर बातों में उलझाकर ओटीपी हासिल किया और उसके क्रेडिट कार्ड से 1.02 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया। हालांकि समय रहते 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने से पुलिस ने पूरी राशि होल्ड करवा दी, जिसे प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़िता को वापस दिलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि महिला को 10 जुलाई को एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को क्रेडिट कार्ड कंपनी का कर्मचारी बताकर कार्ड की लिमिट शुरू कराने की बात कही। कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति ने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया और बातचीत के दौरान महिला से ओटीपी ले लिया। करीब दो सप्ताह बाद 23 जुलाई को जब महिला के पास 1.02 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल पहुंचा, तब उसे ठगी का पता चला। इसके बाद उसने तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। हाल ही में साइबर वित्तीय अपराधों में ई-जीरो एफआईआर की सीमा 5 लाख से घटाकर 1 लाख किए जाने के कारण मामला सीधे साइबर थाना चित्तौड़गढ़ पहुंचा। एसपी धर्मेंद्र यादव के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के सुपरविजन में साइबर थाना प्रभारी मनीष शर्मा और उनकी टीम ने तकनीकी जांच शुरू की। ट्रांजेक्शन की पूरी कड़ी खंगालते हुए जिन बैंक खातों में राशि ट्रांसफर हुई थी, उन्हें चिह्नित कर संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारियों के सहयोग से खाते फ्रीज कर पूरी राशि होल्ड करवा दी गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बैंक, क्रेडिट कार्ड या केवाईसी के नाम पर आने वाली किसी भी अनजान कॉल पर ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या गोपनीय विवरण साझा न करें। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में बिना देरी 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

# अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र पायल की कार्रवाई सवालों के घेरे में, जांच के बाद बाद कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल!!

24 न्यूज अपडेट

सलूंबर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत जयसमंद की ग्राम पंचायत वीरपुरा में कंतोड़ा से घनचौपड़ तक की सड़क के निर्माण में अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र पायल की कार्रवाई गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। अधिकारी ने जिस निर्माण कार्य को मौके पर निरीक्षण के बाद 'शून्य कार्य' बताते हुए तीन इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया था, उसी मामले की बाद में हुई उच्च स्तरीय तकनीकी जांच में मौके पर नया निर्माण कार्य मिलने की बात सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।\

## पूरा काम शून्य घोषित कर दिया

पूरा विवाद जुलाई की शुरुआत में शुरू हुआ। 26 मार्च, 2026 से शुरू हुए सड़क निर्माण कार्य का पहला रनिंग बिल 60 लाख 74 हजार 684 रुपये ठेकेदार मैसर्स जय बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के माध्यम से अधिशासी अभियंता को प्रस्तुत किया गया। अधिशासी अभियंता ने बिल को स्वीकृति के लिए अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र पायल के पास भेजा, लेकिन भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय पायल ने मौके का निरीक्षण कर पूरा कार्य ही 'शून्य' घोषित कर दिया।

## नोटिस जारी कर लगाए आरोप

अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता मणिलाल मेघवाल, सहायक अभियंता विनायक कुमार जांगिड़ और कनिष्ठ अभियंता धर्मराज मेघवाल को नोटिस जारी करते हुए आरोप लगाया कि बिल में दर्शाई गई रिटेनिंग वॉल और पुलिया का निर्माण पहले ही किसी अन्य एजेंसी द्वारा कराया जा चुका है। इसी आधार पर तीनों अधिकारियों से जवाब मांगा गया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। खबर सामने आने के बाद विभाग में हलचल मची और अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर से तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करनी पड़ी।

## जांच समिति के सामने खुल गई दावे की पोल

समिति में अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधीक्षण अभियंता (गुण नियंत्रक) मुनीम चंद्र मीणा और अधिशासी अभियंता (गुण नियंत्रक) मनीष अरोड़ा को शामिल किया गया। समिति ने मौके पर तकनीकी निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में मौके पर नया निर्माण कार्य पाया गया और कार्य को 'शून्य' मानने की बात सही नहीं पाई गई। इसके बावजूद विभाग ने अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की और न ही कोई निर्णय सामने आया।

## ग्रामीण बोले, कहीं कमिशन का तो नहीं चक्कर

इधर विवाद बढ़ने पर ग्राम पंचायत वीरपुरा के ग्रामीण भी खुलकर सामने आ गए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र पायल पर सड़क निर्माण कार्य को अनावश्यक रूप से रोकने और ठेकेदार तथा विभागीय अधिकारियों को परेशान करने के आरोप लगाए। ज्ञापन में कमीशन से जुड़े आरोप भी लगाए गए, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

## क्या आंख मींच कर निकाल दिया निष्कर्ष

मामले में ग्राम पंचायत वीरपुरा और पंचायत समिति जयसमंद की रिपोर्ट ने भी अधीक्षण अभियंता के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि पिछले कई वर्षों में इस मार्ग पर किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। यदि ऐसा है तो फिर अधीक्षण अभियंता ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित निर्माण पहले से मौजूद था और बिल गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

## पथराव के आरोप के दावे की भी निकली हवा

विवाद के बीच अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र पायल ने सलूंबर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताते हुए वाहन पर पथराव का आरोप लगाया तथा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और ठेकेदार को पाबंद किए जाने की मांग की। हालांकि इसी घटना को लेकर उनके चालक द्वारा दिए गए लिखित पत्र में उल्लेख किया गया कि कार के आगे चल रहे डंपर से उछले पत्थर के कारण वाहन का कांच टूटा था। दोनों बयानों के अंतर ने भी नए सवाल खड़े कर दिए।

## क्या रिटायरमेंट तक रिपोर्ट दबाने की कर ली व्यवस्था

सूत्रों के अनुसार जांच समिति अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप चुकी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभागीय हलकों में चर्चा है कि रिपोर्ट उच्च स्तर पर लंबित है। वहीं अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र पायल दो दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे कार्रवाई में देरी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।

## इतनी क्या जल्दी थी नोटिस की, विश्वसनीयता पर उठे गंभीर सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि बाद की तकनीकी जांच में निर्माण कार्य सही पाया गया तो बिना अंतिम जांच के तीन इंजीनियरों को नोटिस जारी करने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? यदि नोटिस का आधार ही तथ्यात्मक रूप से कमजोर साबित होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? पंचायतों की रिपोर्ट, तकनीकी जांच और चालक के बयान के बाद भी विभाग अब तक मौन क्यों है? यह मामला अब केवल 60.74 लाख रुपये के बिल का नहीं, बल्कि विभागीय निर्णय प्रक्रिया, जवाबदेही और तकनीकी निरीक्षण की विश्वसनीयता का बन चुका है।

# नगर निगम चुनाव: कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल, वार्ड स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने की रणनीति तय

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 27 जुलाई। राजस्थान में कैंसर उपचार को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में पारस हेल्थ उदयपुर ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपने व्यापक मल्टी-डिसिप्लिनरी ऑन्कोलॉजी विभाग की विशेषताओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराकर मरीजों को समग्र एवं मरीज-केंद्रित उपचार प्रदान किया जा रहा है। अस्पताल के फैसिलिटी डायरेक्टर अनुभव सुखवानी ने कहा कि पारस हेल्थ का उद्देश्य कैंसर मरीजों को उनके घर के नजदीक ही आधुनिक, समन्वित और विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज में केवल चिकित्सकीय विशेषज्ञता ही नहीं, बल्कि मरीज और उसके परिवार को निरंतर सहयोग एवं समग्र देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विभाग में डॉ. मनोज यू. महाजन (निदेशक, मेडिकल ऑन्कोलॉजी), डॉ. रेनू मिश्रा (प्रिंसिपल कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी), डॉ. सचिन जैन (सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी), डॉ. रोनक जैन (कंसल्टेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी), डॉ. सौरभ शर्मा (सीनियर कंसल्टेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी) तथा डॉ. कीर्ति शिवहरे शर्मा (कंसल्टेंट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) की विशेषज्ञ टीम सेवाएं दे रही है। विशेषज्ञ मरीज की बीमारी के प्रकार, स्टेज और जटिलता के आधार पर संयुक्त रूप से उपचार योजना तैयार करते हैं। अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, एडवांस्ड कैंसर सर्जरी, प्रिसिजन रेडिएशन थेरेपी, सपोर्टिव केयर और फॉलो-अप सेवाएं उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि कैंसर का जल्द पता लगने और समय पर उपचार शुरू होने से मरीजों के स्वस्थ होने की संभावना और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच और कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की।

# राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 28 जुलाई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने राजस्व से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रगति की गहन समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आमजन से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान नामांतरण, सीमांकन, विभाजन, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों सहित अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही संपर्क पोर्टल सहित जन अभाव अभियोग से सम्बंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी राजस्व कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं तथा आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग करते हुए राजस्व कार्यों में गति लाएं और विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को समय पर राहत मिल सके। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) दीपेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) जितेंद्र ओझा सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार मौजूद रहे।

# उदयपुर के 'आर्किटेक्ट्स टॉवर' में बनेगा टाइम कैप्सूल, 2047 में पढ़ेगी अगली पीढ़ी आज के शहर की कहानी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 28 जुलाई। लेकसिटी उदयपुर में निर्माणाधीन 'आर्किटेक्ट्स टॉवर' अब केवल एक स्थापत्य स्मारक नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला अनूठा सांस्कृतिक दस्तावेज भी बनेगा। शोभागपुरा स्थित जे.के. सर्किल पर बन रहे करीब 35 फीट ऊंचे इस टॉवर में 'टाइम कैप्सूल' स्थापित किया जाएगा, जिसमें आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स और उदयपुरवासी अपनी यादें, विचार, रचनाएं और सपने सुरक्षित रख सकेंगे। इस कैप्सूल को 26 जनवरी 2047, यानी भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पर खोला जाएगा।

परियोजना के मुख्य सूत्रधार आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा ने बताया कि यह पहल वर्तमान पीढ़ी की रचनात्मक सोच और संवेदनाओं को भविष्य तक पहुंचाने का प्रयास है। टाइम कैप्सूल में केवल दस्तावेज ही नहीं, बल्कि आज के उदयपुर की सामाजिक, सांस्कृतिक और वास्तु पहचान भी संरक्षित की जाएगी।

### क्या भेज सकते हैं प्रतिभागी?

प्रतिभागी अपने हाथ से बनाए स्केच, वास्तुकला से जुड़ी प्रेरणा पर लेख, पसंदीदा प्रोजेक्ट की कहानी, फोटोग्राफ, डिज़ाइन शीट, ड्रॉइंग या ऐसी कोई स्मृति भेज सकते हैं, जिसे वे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हों। इसके अलावा परिवार का फोटो, वर्तमान निवास का विवरण, आज के उदयपुर पर कविता या लेख तथा भविष्य के उदयपुर की अपनी कल्पना भी भेजी जा सकती है। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ नाम, आयु, व्यवसाय और पूरा पता देना अनिवार्य होगा।

10 अगस्त तक भेजी जा सकेंगी प्रविष्टियां

परियोजना की टेक्नीकल डायरेक्टर प्रियंका कोठारी ने बताया कि यह पहल मुख्य रूप से आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स के लिए शुरू की गई है, लेकिन उदयपुर का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 10 अगस्त तक आर्किटेक्ट सुनील एस. लड्ढा, वर्कस्पेस डिज़ाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर G-1-192, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सुखेर, अर्बन स्क्वायर मॉल के पीछे, उदयपुर के पते पर भेज सकते हैं।

### शहरवासियों में बढ़ा उत्साह

जे.के. सर्किल पर टॉवर का निर्माण तेजी से जारी है। परियोजना को लेकर शहरवासियों में उत्सुकता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग निर्माण स्थल पर पहुंचकर इसकी जानकारी ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण होने के बाद आर्किटेक्ट्स टॉवर भारतीय स्थापत्य परंपरा, विज्ञान और कला का प्रतीक बनने के साथ-साथ उदयपुर की नई पहचान बनेगा।

# शाला दर्पण की स्टाफ विंडो बंद होने से बढ़ी शिक्षकों की परेशानी, विद्यार्थियों की DBT योजनाएं भी अटकीं

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। शाला दर्पण पोर्टल की स्टाफ विंडो पिछले करीब 20 दिनों से तकनीकी समस्याओं से जूझ रही है। इसके विरोध में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव को ज्ञापन भेजकर पोर्टल को नियमित और निर्बाध रूप से संचालित कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि पोर्टल की खराब व्यवस्था से शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि स्टाफ विंडो प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहती है। इसके बाद भी पोर्टल बेहद धीमी गति से चलता है और बार-बार तकनीकी त्रुटियां आने से शिक्षक आवश्यक ऑनलाइन कार्य समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री गोपाल मीणा ने कहा कि वर्तमान में स्टाफ लॉगिन के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार और जन आधार प्रमाणीकरण का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। इसी प्रक्रिया के आधार पर राज्य सरकार की डीबीटी (DBT) योजना के तहत यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, लाडो योजना सहित अन्य छात्र कल्याणकारी योजनाओं की राशि विद्यार्थियों के खातों में भेजी जानी है। तकनीकी बाधाओं के कारण प्रमाणीकरण में देरी होने से हजारों विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिलने में विलंब की आशंका है। संगठन ने यह भी बताया कि शिक्षकों के प्रपत्र-10 अपडेट करने और एपीएआर (2025-26) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। स्टाफ विंडो बंद रहने और सर्वर की धीमी गति के कारण शिक्षक समय सीमा के भीतर अनिवार्य ऑनलाइन कार्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं। में मांग की गई है कि शाला दर्पण की स्टाफ विंडो को पूरे कार्यालयीन समय में नियमित रूप से संचालित किया जाए, पोर्टल की तकनीकी खामियों का स्थायी समाधान किया जाए तथा मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रपत्र-10 और APAR की अंतिम तिथि बढ़ाने पर भी विचार किया जाए।

शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा असर शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थियों को मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक -सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।